



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 1 जुलाई, 2004 / 10 आषाढ़, 1926

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171 002, 1 जुलाई, 2004

संख्या वि० स०-गवर्नमेंट बिल / 1-43 / 2004.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2004 (2004 का विधेयक संख्यांक-14) जो आज दिनांक

1 जुलाई, 2004 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे० आर० गाज़टा,  
सचिव,  
हि० प्र० विधान सभा।

E.P. Secretariat Library

Acc. No. 28000

• Price —

Source —

Date 6/05 Lib 3

## हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2004

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995  
(1995 का 15) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा  
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित संक्षिप्त नाम।  
कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण)संशोधन अधिनियम, 2004 है ।

2. हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, उद्देशिका  
का 15 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' निर्दिष्ट किया गया है) की उद्देशिका में "निवारित करने" शब्दों के पश्चात् "और जीव अनाशित कूड़ा-कचरा सामग्री के उपयोग को विनियमित करने" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,-

धारा 2 का  
संशोधन।

(i) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (कक) अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(कक)" सक्षम प्राधिकारी "से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के प्रवर्तन हेतु नियुक्त कोई प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति अभिप्रेत है";

(ii) विद्यमान खण्ड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे,  
अर्थात्:-

"(ड)" जीव अनाशित कूड़ा-कचरा "से जीव अनाशित सामग्री से निर्मित अपशिष्ट कूड़ा-कचरा अभिप्रेत है; और

“(डड) “जीव अनाशित सामग्री” से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसका, जीवाणु-क्रिया (माइक्रो-ऑर्गानिज्मज), धूप या अन्य प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा विघटन और अवक्रमण नहीं किया जा सकता है और इसके अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पोलीथीन, नाईलोन, या प्लास्टिक के अन्य पदार्थों जैसे कि पॉली-विनायल-कार्बोहाइड्रेटस (पी0वी0सी0), पोलीप्रोपाईलीन और पोली-स्टाइरीन से बनाया गया या निर्मित माल सम्मिलित है;” और

(iii) खण्ड (च) में, विद्यमान उप-खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) को क्रमशः उप-खण्ड (i) (ii) (iii) और (iv) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ”।

धारा 3-क

का जोड़ना। जाएगी, अर्थात:-

4. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी

“3-क. जीव अनाशित सामग्री से विनिर्मित कतिपय चीजों के उपयोग पर निर्बन्धन या प्रतिषेध.—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर उस जीव अनाशित सामग्री के उपयोग पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले सन्नियमों के प्रतिकूल है, निर्बन्धन या प्रतिषेध अधिरोपित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार उन विनिर्माताओं, वितरकों और अन्य व्यक्तियों पर, जो वस्तुओं का उत्पादन या हथालन (हैंडलिंग) करते हैं, आकार (टाईप), माप (साइज), लेवलिंग और कम्पोजिशन पैकेजिंग की बाबत, सामग्री की निम्नीकरणीयता और पुनः चक्रणियता के लिए मानकों या सन्नियमों सहित इसके उपयोग और निपटारे की बाबत अपेक्षाएं अधिरोपित कर सकेगी।”।

धारा 6 का

प्रतिस्थापन। अर्थात् :-

5. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,

“6. जीव अनाशित कूड़ा-कचरा या जीव अनाशित सामग्री हटाने के लिए स्थानीय प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी की शक्ति.—स्थानीय प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी किसी ऐसी भूमि या भवन, जो जीव अनाशित कूड़े-कचरे या जीव अनाशित सामग्री का अनधिकृत ढेर लगाने या जमा करने का स्थान बन गया है जिससे न्यूसैन्स का कारण बनने की सम्भावना है या जल निकास या मल व्ययन प्रणाली को क्षति होने की सम्भावना है या

जीवन अथवा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने की सम्भावना है, के स्वामी या अधिभोगी या भागिक स्वामी या उसका स्वामी या भागिक स्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति को लिखित में नोटिस देने के पश्चात्, इस प्रकार ढेर लगाए गए या संगृहीत तथाकथित कूड़े-कचरे या सामग्री को हटाएगा या हटवाएगा या ऐसे पग उठाएगा जैसे वह आवश्यक समझे, और तथाकथित कूड़े-कचरे या सामग्री का, ऐसे व्यक्ति के खर्च पर, इस अधिनियम की धारा 7-क की उप धारा (5) में यथा उपबंधित रीति में, निपटारा कर सकेगा ।” ।

6. मूल अधिनियम की धारा 7 में खण्ड (ज) का लोप किया जाएगा । धारा 7 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:— धारा 7-क का जोड़ना ।

**“7-क. प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति.—**(1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा सशक्त किसी व्यक्ति को, सभी युक्तियुक्त समयों पर ऐसी सहायता के साथ, जैसी वह आवश्यक समझे, किसी भी स्थान पर, निम्नलिखित के लिए, प्रवेश करने का अधिकार होगा—

(क) राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गये किसी भी कृत्य के अनुपालन के प्रयोजन के लिए; या

(ख) यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या ऐसे किन्हीं कृत्यों का अनुपालन किया जाना है, यदि ऐसा है तो किस रीति में, या क्या इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध या इस अधिनियम के अधीन तामील किए गए किसी नोटिस, किए गए किसी आदेश, दिए गए किसी निदेश या अनुदत्त किसी प्राधिकार का अनुपालन किया जा रहा है या किया गया है; या

(ग) किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य तात्त्विक सामग्री के परीक्षण या किसी भवन की तलाशी, जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण है, कि इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा

है या किया जाने वाला है, के संचालन तथा ऐसे अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य तात्विक सामग्री, जिसके बारे में इसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि यह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य दे सकेगा, के अभिग्रहण, के प्रयोजन के लिए।

(2) किसी भी जीव अनाशित सामग्री या जीव अनाशित कूड़े-कचरे का हथालन (हैंडलिंग) करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उप-धारा (1) के अधीन सशक्त व्यक्ति को, उस उप-धारा के अधीन कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए, समस्त सहायता प्रदान करने के लिए आबद्ध होगा और यदि वह बिना किसी युक्तियुक्त हेतुक या कारण से ऐसा करने में असफल रहता है तो वह इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति, उप-धारा (1) के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति को, उसके कृत्यों के अनुपालन में जानबूझ कर विलम्ब करवाता है या बाधा डालता है, तो वह इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय होगा।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध यावत्शक्य, इस धारा के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को वैसे ही लागू होंगे, जैसे वह उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण के लिए लागू होंगे। 1974 का 2

(5) इस धारा के अधीन अभिगृहीत किसी जीव अनाशित कूड़े-कचरे या जीव अनाशित सामग्री का निपटारा, ऐसी रीति में किया जाएगा, जैसी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

धारा 8 का  
संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) में, "एक मास" और "पांच हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "तीन मास" और "पच्चीस हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 11 का  
संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) में, "ऐसा अधिकारी विनिर्दिष्ट करे" शब्दों के स्थान पर "राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे", शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

धारा 12 का  
संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 12 में, "स्थानीय प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "सक्षम प्राधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति" चिन्ह और शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

11. मूल अधिनियम की धारा 15 में "स्थानीय प्राधिकरण" शब्दों के धारा 15 का पश्चात्, जहां-जहां वे आते हैं, "या सक्षम प्राधिकारी" शब्द अन्तः स्थापित किए संशोधन। जाएंगे ।

12. मूल अधिनियम की विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची का अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात:- प्रतिस्थान।

### **\*अनुसूची**

[ (धारा 2 (डड) देखें ) ]

जीव अनाशित सामग्री की सूची

1. पोलिथीन ।
2. नाईलोन ।
3. पोलिविनायल-कार्बोहाइड्रेट्स (पी0वी0सी0) ।
4. पोलि-प्रोपाईलीन ।
5. पोलि-स्टाइरीन । " ।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 जीव अनाशित कूड़े-कचरे को अव्यवस्थित रूप से फेंकने या जमा करने के निवारण को परिकल्पित करता है। यद्यपि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 (ज) के अधीन किस्म, प्रकार, लेबल लगाना और पैकेजिंग की संरचना की बाबत, जिसका उपयोग वस्तुओं का हथालन (हैंडलिंग) करने वाले विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा, अपेक्षाएँ अधिरोपित करने का उपबन्ध है परन्तु वर्तमानतः उपरोक्त अधिनियम में जीव अनाशित सामग्री के उपयोग पर प्रतिषेध का सुव्यक्त उपबन्ध विद्यमान नहीं है। क्योंकि जीव अनाशित कूड़े-कचरे के अनुचित निपटारे के अपराध का व्यवहारिक रूप से पता लगाना मुश्किल है, इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में ऐसा उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया है जो जीव अनाशित सामग्री के प्रयोग पर प्रतिबन्ध और प्रतिषेध लगाने के लिए राज्य सरकार को स्पष्टतया समर्थ बनाए।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 6 में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबन्धों के अनुसार केवल स्थानीय प्राधिकरण कूड़े-कचरे या प्रतिषिद्ध किस्म की सामग्री, जो ऐसे स्थान में इकट्ठी की गई है, को हटाने के लिए सक्षम है। यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारियों को, बरामद जीव अनाशित कूड़े-कचरे या जीव अनाशित सामग्री को ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेगी, हटाने या निपटाने के लिए भी सशक्त किया जाना चाहिए।

क्योंकि इस अधिनियम के अधीन अपराध का पता चलने पर, परिसरों में प्रवेश और निरीक्षण अपेक्षित हो सकेगा, इसलिए नई धारा 7-क अन्तः स्थापित की जा रही है। उस भारी नुकसान, जो जीव अनाशित कूड़ा-कचरा या जीव अनाशित सामग्री हमारे आस-पास (सराउन्डिंगज़) को पहुंचाती है, को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन अधिकथित विद्यमान शास्तियां अपर्याप्त प्रतीत होती हैं इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन न हो, शास्ति उपबन्ध और अधिक कठोर बनाने तथा कारावास को एक मास से बढ़ा कर तीन मास करने और अधिकतम जुर्माने को पांच हजार रुपए से बढ़ा कर पच्चीस हजार रुपये करने का भी विनिश्चय किया गया है।

विवेकाधिकार के निराकरण के लिए यह आवश्यक है कि प्रशमन की राशि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरमद्र सिंह,  
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख—, 2004



## वित्तीय ज्ञापन

---शून्य---

-----

## प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 4 और 7 राज्य सरकार को जीव अनाशित सामग्री के उपयोग तथा निरीक्षण के दौरान अभिगृहीत सम्पत्ति के व्ययन हेतु सन्नियमों का उपबन्ध करने के लिए, सशक्त करते हैं । यह प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है ।

-----

**हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2004**

हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 (1995 का 15) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

वीरमद्र सिंह,  
मुख्य मंत्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,  
सचिव (विधि) ।

शिमला :

तारीख : \_\_\_\_\_, 2004

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 14 of 2004.**

**THE HIMACHAL PRADESH NON-BIODEGRADABLE  
GARBAGE (CONTROL) AMENDMENT BILL, 2004**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*to amend the Himachal Pradesh Non-Biodegradable  
Garbage (Control) Act, 1995 (Act No. 15 of 1995).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fifth Year of the Republic of India, as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Non- Short title.  
Biodegradable Garbage (Control) Amendment Act, 2004.

15 of 1995 2. In preamble of the Himachal Pradesh Non- Amendment  
Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995, (hereinafter referred of  
to as the “principal Act”), after the words “public view”, the words Preamble.  
and sign “and to regulate the use of non-biodegradable material”  
shall be inserted.

3. In section 2 of the principal Act,— Amendment  
of section 2.

(i) after clause(a), the following clause (aa) shall be  
inserted, namely :-

“(aa) “competent authority” means any authority,  
officer or person appointed by the State Government,  
by notification, for enforcement of any of the  
provisions of this Act;”;

- (ii) for existing clause (e), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(e) “non-biodegradable garbage” means the waste garbage made of non-biodegradable material; and

(ee) “non-biodegradable material” means the material which cannot be decomposed or degraded by action of micro-organisms, sunlight or other natural actions and includes goods made or manufactured from polythene, nylon or other plastic substances such as Poly-vinyl-carbohydrates (P.V.C.), poly-propylene and polystyrene specified in the Schedule to this Act;” and

- (iii) in clause (f), the existing sub-clauses (a), (b), (c) and (d) shall respectively be renumbered as sub-clauses (i), (ii), (iii) and (iv).

Addition  
of section  
3-A.

4. After section 3 of the principal Act, the following section shall be added, namely:—

**“3-A.. Restriction or prohibition on use of certain things manufactured from non-biodegradable material.—(1)**

The State Government may, by notification, impose restriction or prohibition on the use of non-biodegradable material within the State of Himachal Pradesh, which is contrary to the norms as the State Government may, by notification, specify.

- (2) The State Government may impose requirements on manufacturers, distributors and other persons, who produce or handle commodities, with respect to the type, size, labelling and composition of packaging with respect to its use and disposal including standards or norms for material degradability and re-cyclability.”.

---

## FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

---

### MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 4 and 7 of the Bill seek to empower the State Government to provide for the norms for the use of non-biodegradable material and for the disposal of property seized during inspection. These delegations of powers are essential and normal in character.

---

**THE HIMACHAL PRADESH NON-BIODEGRADABLE GARBAGE  
(CONTROL) AMENDMENT BILL, 2004**

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act,  
1995 (Act No. 15 of 1995).

VIRBHADRA SINGH,  
*Chief Minister.*

---

SURINDER SINGH THAKUR,  
*Secretary (Law).*

SHIMLA :

*The* , 2004